कमीशन प्राप्त अधिकारी समान कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सैनिक मेरिट सूची में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। नियम 5 के खंड (2) के अनुसार, नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त और किसी विशेष वर्ष के लिए आवंटित सभी उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी है। इस प्रकार, एक सैनिक जो योग्यता के क्रम में नंबर 1 पर हो सकता है और जिसका जन्म आपातकालीन कमीशन अधिकारी से पहले हुआ हो, वह वरिष्ठ होगा। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा नियमों पर रखी गई व्याख्या के अनुसार, वरिष्ठता के उद्देश्य से केवल अधिकारी ही सैन्य सेवा का लाभ पाने का हकदार होगा। यदि यह विवाद स्वीकार कर लिया गया तो अधिकारी वरिष्ठ हो जायेगा। परिणाम खण्ड (2) के तहत सोचे गए विचार के विपरीत होगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा नियमों पर रखी गई व्याख्या विरोधाभासी परिणाम देगी।

(21) उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि प्रतिवादी नियम 5 के तहत स्वीकार्य वरिष्ठता के लाभ का हकदार था, इस तथ्य के बावजूद कि उसे आपातकालीन कमीशन अधिकारी या शॉर्ट सर्विस नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में जारी नहीं किया गया था।

(22) परिणामस्वरूप, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं क्योंकि रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, निर्णय उन कारणों पर आधारित है जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए कारणों से भिन्न हैं। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

जेएसटी

न्यायमूर्ति, के.के श्रीवास्तव के समक्ष

रविंदर सिंह, -याचिकाकर्ता

बनाम

जनमेजा सिंह एवं अन्य, -प्रतिवादी

E.P. No. 4 of 1997

3 जून 1999

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस.एस. 80, 81 और 100—चुनाव याचिका में दलीलें—क्या मुकदमे की दलीलों से अलग हैं—भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया—निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप—याचिका में उसे उन दावों से जोड़ने

का कोई दावा नहीं—चुनाव याचिका की विचारणीयता।

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी मुकदमे में दलीलों से संबंधित कानून चुनाव याचिका में दिए गए बयानों से संबंधित कानून से पूरी तरह से अलग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों में स्पष्ट रूप से कहा है |

यह विचार किया गया कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों और चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवरणों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। चुनाव याचिका दायर करने के बाद भ्रष्ट आचरण से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य को स्पष्ट करने या जोड़ने वाले किसी भी आधार में संशोधन कानूनन अनुमति योग्य नहीं है।

(पैरा 42)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है , चुनाव याचिका में दिए गए कथनों में किसी भी तरह के झूठे आरोप का अभाव है और श्रीमती रूपिंदर कौर द्वारा कथित तौर पर दिए गए प्रतिनिधित्व के पीछे या अधिकारियों के साथ मामले को उठाने में प्रतिवादी नंबर 1 की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी के बारे में पूर्ण और बेहतर विवरण नहीं है। इसके अलावा, यह समाचार, जो वर्तमान मामले में मतदान की तारीख से बहुत पहले यानी सात साल से अधिक समय पहले 16 सितंबर, 1989 को प्रकाशित हुआ था, फरवरी, 1997 के चुनावों में याचिकाकर्ता की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना नहीं थी। . यह समाचार फरवरी, 1997 के चुनावों से बहुत दूर से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता को हराकर निर्वाचित घोषित किया गया था।

(पैरा 23)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है ,चुनाव याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, पंजाब की ओर से पैम्फलेट प्रकाशित करवाया था या वह किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त पैम्फलेट के प्रकाशन से संबंधित था। चुनाव याचिका में इस पैम्फलेट के प्रकाशन और प्रतिवादी नंबर 1 को इससे जोड़ने के संबंध में भौतिक तथ्यों और संपूर्ण विवरणों का अभाव है। इसके अलावा, इस पैम्फलेट में कोई तारीख का उल्लेख नहीं है, हालांकि यह 7 फरवरी, 1997 को होने वाले मतदान को संदर्भित करता है। चुनाव याचिका के प्रयोजन के लिए वह यह नहीं मान सकते कि चूंकि पैम्फलेट में मतदाताओं से प्रतिवादी को वोट देने की अपील की गई है। क्रमांक 1, उक्त पांच लाख कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा उनकी सहमति से तैयार या जारी किया गया था।(पैरा 28)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि चुनाव याचिका में कार्रवाई का कोई

कारण नहीं बताया गया है और इस आधार पर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
(पैरा 59)

गुलशन शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए एचएस हुडा वरिष्ठ वकील , एमएल सग्गर वकील

निर्णय

न्यायमूर्ति के.के श्रीवास्तव,

(1) याचिकाकर्ता रविंदर सिंह ने पंजाब विधान सभा के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी, 1997 में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 96, फिरोजपुर कैंट से चुनाव लड़ा। प्रतिवादी संख्या 1, श्री जनमेजा सिंह, एक उम्मीदवार थे। उक्त चुनाव अकाली दल (बादल) द्वारा स्थापित किया गया था। मतदान 7 फरवरी 1997 को हुआ था। मतगणना 9 फरवरी 1997 को हुई थी। कुल मिलाकर छह उम्मीदवार थे, जो पंजाब राज्य की विधान सभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के अलावा मैदान में अन्य उम्मीदवार प्रतिवादी नंबर 2 से 5 थे, अर्थात् लाई सिंह, खैराती लाई, गुरप्यार सिंह और रतिंदर सिंह। रिटर्निंग ऑफिसर ने श्री जनमेजा सिंह को अन्य उम्मीदवारों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल करने के कारण पंजाब राज्य की विधान सभा का विधिवत निर्वाचित सदस्य घोषित किया। प्रतिवादी नंबर 1 को 38281 वोट मिले जबकि याचिकाकर्ता को 36,551 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों को निम्नानुसार वोट प्राप्त हुए:-

नाम	नं. डाले गए वोटों की संख्या उम्मीदवार का पक्ष
श्री लाई सिंह पुत्र श्री नागिंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 2)	7,840
श्री खरैतीलाई पुत्र श्री देवराजलाई (प्रतिवादी संख्या 3)	314
गुरप्यार सिंह पुत्रे अर्जन सिंह (प्रतिवादी संख्या 4)	65
रतिंदर सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 5)	3,753

(2) प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को 1730 मतों के अंतर से हराया। चुनाव में कुल 8794 वोट पड़े(7. अवैध वोटों की संख्या 1143 थी और वैध वोटों की कुल संख्या 86804 थी।

(3) याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका दायर कर उसमें उल्लिखित विभिन्न आधारों पर लौटे उम्मीदवार/प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव को अवैधानिक घोषित करने की मांग की और आगे की घोषणा के लिए कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 भ्रष्ट आचरण करने का दोषी है और छह साल की अवधि के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि वह उक्त निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित हुआ है।

(4) याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये कथित भ्रष्ट आचरण के आरोपों का उल्लेख किया गया था। इन आरोपों को तथ्यों के दो सेटों में रखा जा सकता है। तथ्यों का पहला सेट यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता की छवि खराब करने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के बीच अनुलग्नक ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6 और ए7 की फोटोस्टेट प्रतियां वितरित कीं। सार्वजनिक। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन अनुलग्नकों की सामग्री इतनी विनाशकारी थी कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने, जिन्होंने इन अनुलग्नकों (ए1 से ए 7) को पढ़ा, या तो बिल्कुल भी मतदान नहीं करने का फैसला किया और किसी भी मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं थे। यह आरोप लगाया गया था कि इन अनुलग्नकों का प्रसार उक्त चुनावों में याचिकाकर्ता की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए एक सोची-समझी चाल से किया गया था। तथ्यों के इस सेट के संबंध में दिए गए कथन पैराग्राफ 9(i), 9(ii), 11 से 27 में निहित हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के

आरोप के संबंध में तथ्यों का दूसरा सेट नकद राशि वितरित करने के बारे में है। उनके समर्थकों को ऐसे मतदाताओं को दिए जाने के लिए, जो उक्त चुनाव में प्रतिवादी नं.एल. के पक्ष में मतदान करने के लिए सहमत होंगे। ये आरोप पैराग्राफ 28 से 39 में निहित हैं। पैरा 40 में, इस संबंध में तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि पैराग्राफ 28 से 39 में उल्लिखित सामग्री से, यह संदेह से परे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 रुपये देकर 3575 वोट खरीदे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 7.5 लाख रुपये और उन्होंने पूरी रात पैसे बांटने में बिताई और किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण किया।

(5) लौटे उम्मीदवार/प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के संबंध में उनके खिलाफ याचिका में लगाए गए आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया। एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि पैराग्राफ 5 से 7, 9, 10, 12 से 14ए, 15 से 21, 23, 24 और 26 से 40 को अनावश्यक, अप्रासंगिक, झूठा, तुच्छ, काल्पनिक और मनगढ़ंत होने के कारण हटाया जा सकता था और चुनाव याचिका की सुनवाई के लिए कार्रवाई के पूरे कारण का खुलासा नहीं करना। यह भी तर्क दिया गया कि पैराग्राफ 6, 7, 9, 10, 12 और 13 में दिए गए कथन कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करते हैं। शेष अनुच्छेदों के संबंध में यह आरोप लगाया गया कि वे झूठे, काल्पनिक और मनगढ़ंत थे और उन कथनों पर चुनाव याचिका का परीक्षण कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। योग्यता के आधार पर, याचिका में लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया।

(6) पक्षों की दलीलों पर, 12 सितंबर, 1997 को छह मुद्दे तय किए गए। प्रतिवादी संख्या के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मुद्दे संख्या 4 और 5 को प्रारंभिक माना जाए और याचिका को साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किए जाने से पहले सुना जाए। मुद्दे संख्या 4 और 5 को निम्नानुसार तैयार किया गया था।

(4) क्या याचिका के पैरा 5 से 7, 9 से 12 और 14 में दिए गए कथन अनावश्यक होने और कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं करने के कारण हटाए जाने योग्य हैं?

(5) क्या चुनाव याचिका में धारा 100 (1) (डी) (iv) के साथ पठित धारा 83 के अर्थ के तहत प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव को रद्द करने के लिए कार्रवाई का पूरा कारण बनाने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों और विवरणों का अभाव है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 ?

7)) इसके बाद, श्री एचएस मत्तेवाल को पता चला कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने 14 जुलाई, 1998 को याचिकाकर्ता द्वारा वोटों की पुनर्गणना से संबंधित प्रार्थना के लिए दबाव नहीं डालने के बारे में एक बयान दिया था और कहा था कि याचिका के किसी भी पैराग्राफ में इस संबंध में दिए गए कथन गलत हो सकते हैं। दबाया नहीं गया माना गया। इस कथन को ध्यान में रखते हुए, अंक संख्या 3, जिसे प्रारंभ में निम्नानुसार तैयार किया गया था: -

3) क्या वोटों की गिनती में अवैधताएं/अनियमितताएं की गईं (जैसा कि चुनाव याचिका के पैरा 9 के उप-पैरा (iii), (iv) और (vi) में आरोप लगाया गया है, जैसे:—

(i) याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए वोट अनुचित तरीके से खारिज कर दिए गए, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

(ii) याचिकाकर्ता के पक्ष में अंकित वोटों को गलत तरीके से प्रतिवादी नंबर 1/लौटे हुए उम्मीदवार के पक्ष में गिना गया, यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

दिनांक 16 दिसंबर 1998 के आदेश द्वारा हटा दिया गया था। अंक संख्या 3 को हटाने के परिणामस्वरूप, शेष अंक संख्या 4, 5 और 6 को क्रमशः अंक संख्या 3, 4 और 5 के रूप में पुनः क्रमांकित करने का आदेश दिया गया था। अंक संख्या 4, जिसे संख्या 3 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, को भी इस प्रकार पुनः पढ़ा गया:-

(3) क्या चुनाव याचिका के पैराग्राफ 7, 9(i) और (ii), 10, 11, 12 और 14 में दिए गए कथनों को अनावश्यक और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करने वाला मानकर खारिज किया जा सकता है?

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने पुनर्गठित मुद्दे संख्या 3 और पुनर्संख्यांकित मुद्दे संख्या 4 पर अपने तर्कों को संबोधित किया।

(9) जहां तक मुद्दे नंबर 3 का सवाल है, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील का तर्क यह है कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ 7, 9(i), 9(ii), 10 से 12 और 14 में दिए गए कथन सही हैं। अनावश्यक होने और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करने के कारण इसे हटाया जा सकता है। मुद्दा संख्या 4 चुनाव याचिका के बारे में है जिसमें धारा 100(1) (डी) के साथ पढ़ी गई धारा 83 के अर्थ में प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को रद्द करने के लिए कार्रवाई का पूरा कारण बनाने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों और विवरणों का अभाव है। iv) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123। मैं अंक संख्या 3 में उल्लिखित विभिन्न अनुच्छेदों में दिए गए कथनों पर विचार करूंगा कि क्या उन्हें अनावश्यक होने और कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करने के कारण हटा दिया जा सकता है। चुनाव याचिका के पैरा 7 में अन्य बातों के साथ-साथ लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:-

"कि प्रतिवादी नंबर 1 ने मतदान से एक दिन पहले और साथ ही वोटों की गिनती के समय विभिन्न अनियमितताएं कीं ताकि उन्हें आसानी से निर्वाचित घोषित किया जा सके।"

(10) पैरा 9(i) और 9(ii) में, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार आरोप लगाया: -

"9. याचिकाकर्ता का कहना है कि लौटे उम्मीदवार श्री का चुनाव। जनमेजा सिंह प्रतिवादी नंबर 1, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों पर अमान्य है और अधिनियम की धारा 100 के तहत खारिज किए जाने योग्य है।:-

(i) कि लौटाए गए उम्मीदवार, उसके एजेंटों और अन्य व्यक्तियों द्वारा लौटाए गए उम्मीदवार की सहमति से तथ्यों के विभिन्न बयानों के प्रकाशन और धन के वितरण की भ्रष्ट प्रथाएं जो गिरती हैं और जो याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण से संबंधित हैं, जो झूठ माना जाता है और सच नहीं माना जाता, फोटोस्टेट कराया जाता और बांट दिया जाता। ऐसी सामग्री की गणना स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए की गई थी। इस तरह की भ्रष्ट प्रथाओं के भौतिक तथ्य और पूर्ण विवरण इस याचिका के अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं।

(ii) याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जहां तक चुनाव के परिणाम का सवाल है तो यहां दिए गए विभिन्न आधारों पर रिटर्न किए गए उम्मीदवार पर भौतिक प्रभाव पड़ा है और सबूतों की जांच करने पर यह पाया जाएगा कि यह लौटा हुआ उम्मीदवार नहीं बल्कि याचिकाकर्ता है। निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार है। इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अधिनियम की धारा 100 के तहत रद्द किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 101 के तहत एक घोषणा का दावा करता है कि याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित किया गया है, क्योंकि वास्तव में, याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित होने का हकदार है।

(11) चुनाव याचिका का पैरा 10 इस प्रकार है:-

"इस याचिका में उठाए गए सभी आधारों पर असर डालने वाले कुछ भौतिक तथ्य इस स्तर पर सुविधा और बेहतर समझ के लिए बताए जा सकते हैं।

(1) याचिकाकर्ता एक कृषक है और 1980 से राजनीति में बहुत रुचि ले रहा है जब वह मार्केट कमेटी, फिरोजपुर कैंट, तहसील और जिला फिरोजपुर का सदस्य बन गया। 1983 में याचिकाकर्ता जिला युवा कांग्रेस, फिरोजपुर के अध्यक्ष बने। 1984 में याचिकाकर्ता मालवा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर का प्रबंधक बन गया और उसके बाद 1986 में याचिकाकर्ता दशमेश का अध्यक्ष बन गया। पब्लिक स्कूल, फ़िरोज़पुर शहर। 1988 में याचिकाकर्ता जिला कुश्ती संघ, फिरोजपुर का अध्यक्ष बन गया। 1989 में याचिकाकर्ता "पंजाब प्रदेश कांग्रेस किसान दल" का महासचिव बन गया। 1991 में याचिकाकर्ता ने पंजाब का निरस्त विधानसभा चुनाव 96-फिरोजपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। 1992 में याचिकाकर्ता ने विधानसभा चुनाव लड़ा और फिरोजपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का राजनीति में बहुत लंबा और उत्कृष्ट करियर है।

(12) याचिका का पैरा 11 इस प्रकार है:-

"राजनीति के लंबे करियर के दौरान याचिकाकर्ता को लगातार अपने विरोधियों, विशेष रूप से प्रतिवादी नं.1. के विरोध का सामना करना पड़ा है, यानी एक लौटा हुआ उम्मीदवार जिसने 1991 में पंजाब के निरस्त विधानसभा चुनाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ 96-पंजाब के फिरोजपुर कैंट विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। 1991 में याचिकाकर्ता के खिलाफ 96-फ़िरोज़पुर कैंट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अकाली दल (बादल) के उम्मीदवार के रूप में। प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले वर्ष 1989 में तत्कालीन अकाल तख्त जत्थेदार श्री दर्शन सिंह को गुमराह करके याचिकाकर्ता को बदनाम करने की साजिश रची थी और 16 सितंबर, 1989 को दैनिक ट्रिब्यून में एक समाचार प्रकाशित किया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी का बयान

तत्कालीन अकाल तख्त जत्थेदार श्री दर्शन सिंह ने इस आशय का एक बयान दिया कि 16 सितंबर, 1989 को दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार गलत है और याचिकाकर्ता और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनाया गया है और याचिकाकर्ता का बयान आरोपों से इनकार कर रहा है। 17 सितंबर, 1989 को दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार श्री दर्शन सिंह को अपना बयान वापस लेने के लिए कहा था, अन्यथा वह मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

(13) चुनाव याचिका के पैरा 12 में निम्नानुसार आरोप लगाया गया है:-

"याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के विरुद्ध लौटे उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण के भौतिक तथ्य और पूर्ण विवरण इस प्रकार हैं: -

क. यह कि 16 सितंबर, 1989 और 17 सितंबर, 1989 के दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचारों की बड़ी संख्या में

फोटो प्रतियां निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव और कस्बे में वितरित की गईं। इन समाचारों में याचिकाकर्ता के खिलाफ बेहद अपमानजनक और पूरी तरह से गलत बयान दिए गए हैं। ऐसे झूठे तथ्य और अपमानजनक बयान इस प्रकार थे ::—

(i) 16 सितंबर, 1989 के समाचार में याचिकाकर्ता को भूमि हड़पने वाला बताया गया और प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव से एक दिन पहले निर्वाचन क्षेत्र में इस समाचार की फोटो प्रतियां वितरित कीं और याचिकाकर्ता को भूमि हड़पने वाला करार दिया।

ख (i) प्रतिवादी नंबर 1 ने 17 सितंबर, 1989 को ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार भी वितरित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार को अपने बयान को वापस लेने की चुनौती दी थी, जिसके तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा. इस समाचार को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से में वितरित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दृढ़ता से बताया था कि याचिकाकर्ता ने अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार को चुनौती दी थी, इसलिए किसी भी निकाय को वोट नहीं देना चाहिए। इस तरह से चुनाव में लौटे उम्मीदवार ने चुनाव में अकाल तख्त की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, ताकि चुनाव में उनकी संभावनाएं उज्ज्वल हो जाएं और याचिकाकर्ता चुनाव में हार जाए।

दैनिक ट्रिब्यून, चंडीगढ़ में 16 सितंबर, 1989 और 17 सितंबर, 1989 को प्रकाशित ये समाचार इस याचिका के साथ अनुलग्नक एजे1 और ए/2 के रूप में संलग्न किए जा रहे हैं।

(ii) प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव और कस्बे में 31 अक्टूबर, 1996 को पंजाबी ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार की बड़ी संख्या में फोटो प्रतियां भी वितरित कीं, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर उपाध्यक्ष मेहर सिंह संधू को पीटने का आरोप लगाया गया है। , शिरोमणी अकाली दल बादल, फिरोजपुर और उनके बेटे, पत्नी और बहू सहित उनके परिवार के सदस्यों और इस समाचार में सम्मानित लोगों को याचिकाकर्ता का 'गुंडा' करार दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इस समाचार की बड़ी संख्या में प्रतियों के वितरण का उद्देश्य चुनाव में उसकी संभावनाओं को उज्ज्वल करना और चुनाव में याचिकाकर्ता की संभावनाओं को हराना था। वास्तव में प्रसारित मूल फोटो कॉपी में से एक को इस याचिका के साथ अनुबंध AJ3 के रूप में दायर किया जा रहा है। इस समाचार का अंग्रेजी अनुवाद Annexure AJ4 है।

(iii) प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव से एक दिन पहले संयुक्त कर्मचारी पंजाब के मोर्चे द्वारा जारी किए गए कथित तौर पर निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव और कस्बे में एक पैम्फलेट की बड़ी संख्या में फोटो प्रतियां भी वितरित की हैं, जिसमें गलत बयान दिया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ तथ्य बनाए गए हैं. इन पर्चों में याचिकाकर्ता को भ्रष्ट बताया गया है, साथ ही कर्मचारियों को धमकाने, परिवारों को बेदखल करने और गुंडागर्दी फैलाने का भी आरोप लगाया गया है. प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से में खुले तौर पर घोषणा की कि यह पर्चा पंजाब के पांच लाख कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा जारी किया गया है और इस तरह प्रतिवादी नंबर 1 ने मतदाताओं की नजर में याचिकाकर्ता की छवि को कम कर दिया है। ताकि चुनाव में उनकी संभावनाएं उज्ज्वल हो सकें। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रसारित इस पैम्फलेट की मूल फोटो कॉपी में से एक को इस याचिका के साथ एक अनुलग्नक AJ5 और इसका वास्तविक अनुवाद AJ6 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

(iv) प्रतिवादी नंबर 1 ने तत्कालीन अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, फिरोजपुर, श्री गुरनैब सिंह बराड़ द्वारा 30 जून, 1990 को जारी एक पत्र की बड़ी संख्या में फोटो प्रतियां भी वितरित की हैं, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत बयान दिया गया है। इस आशय का ■ कि पुलिस में चोरी का एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है

याचिकाकर्ता के खिलाफ थाना घाल खुर्द में मामला दर्ज किया गया और यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में पूछताछ के लिए सीआईए स्टाफ, फिरोजपुर द्वारा हिरासत में लिया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव से एक दिन पहले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में गाँवों और कस्बों का दौरा करके खुलेआम घोषणा की कि इस पत्र में याचिकाकर्ता को उनकी ही पार्टी के नेता, आईओ श्री गुरनियाब सिंह बराड़ द्वारा अपराधी करार दिया गया है। इस पत्र की फोटो प्रतियां वितरित करके प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव में अपनी संभावनाओं को उज्ज्वल करने और चुनाव में याचिकाकर्ता की संभावनाओं को हराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को गुमराह किया है और इस तरह वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण में शामिल हो गया है। . वास्तव में प्रसारित मूल फोटो प्रतियों में से एक को इस याचिका के साथ अनुबंध AJ7 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

(v) यह कि अनुलग्नक ए/1 से एजे7 में उल्लिखित सामग्री झूठी है और सत्य नहीं है और समय-समय पर याचिकाकर्ता के खिलाफ साजिश रची गई है ताकि जनता की नजरों में उसकी छवि खराब हो सके। सामग्री इतनी विनाशकारी है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने, जिन्होंने इन फोटो प्रतियों को पढ़ा, अनुलग्नक ए/1 से एजे7 तक, या तो बिल्कुल भी वोट न देने का फैसला किया और किसी भी मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं थे और इस प्रकार इन बयानों की गणना स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के निर्वाचित होने की संभावनाओं पर

प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए की गई थी।

(vi) प्रतिवादी नंबर 1 और उसके समर्थकों अर्थात् फिरोजपुर कंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह उर्फ जिंदू ने संयुक्त रूप से निशान सिंह और याचिकाकर्ता के अन्य समर्थकों को फिरोजपुर कैंट शहर में सुबह के समय यानी लगभग 8 बजे पीटा। मतदान अर्थात 7 फरवरी 1997, ताकि शहर के शहरी मतदाताओं को आतंकित किया जा सके और इस तरह शहर के बड़ी संख्या में मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में परेशानी को भांपते हुए मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले और इस प्रकरण में फ़िरोज़पुर छावनी, वह भी शहर के मध्य में, यानी छावनी बोर्ड का स्कूल फ़िरोज़पुर कैंट। अमर टॉकीज फिरोजपुर कैंट के पास जानबूझकर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इंजीनियर किया गया था ताकि याचिकाकर्ता के चुनाव की संभावनाओं को हराया जा सके।

(14) Paraparaoi13hof the;telectionitpetition1 ने निम्न आरोप लगाए

"यह कि लौटे उम्मीदवार और उनकी सहमति से उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने समाचार की उपरोक्त फोटो प्रतियां वितरित कीं

6 फरवरी, 1997 को पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आइटम और पैम्फलेट, यानी अनुलग्नक ए/1 से ए/7। लौटे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी उपस्थिति में समाचार आइटम और पैम्फलेट ए/1 से ए/7 की फोटो प्रतियां वितरित कीं। "

पैरा 14 में लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:-

"लौटे हुए उम्मीदवार ने समाचार सामग्रियों और पैम्फलेटों की उपरोक्त फोटो प्रतियां, यानी अनुलग्नक ए 1 से ए/7 तक कई स्थानों पर स्वयं वितरित कीं और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में वितरण की व्यवस्था की। हालाँकि, याचिकाकर्ता अपने मामले को केवल उन्हीं स्थानों तक सीमित रखना चाहता है, जहाँ से लौटाया गया उम्मीदवार स्वयं समाचार वस्तुओं और पैम्फलेटों की उपरोक्त उल्लिखित फोटो प्रतियाँ वितरित करता हुआ पाया गया। ए 1 से ए/7 जहां इन्हें उनकी उपस्थिति में लौटे उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा वितरित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उनकी सहमति दर्शाता है।

6 फरवरी, 1997 को प्रातः लगभग 8.30 बजे उम्मीदवार निम्नलिखित के साथ लौटे:—

1. मेहर सिंह संधू पुत्र भाग सिंह निवासी बस्ती भाग सिंह।
2. बाबू सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम वादनी गुलाब सिंह:

और कुछ अन्य लोगों ने गांव रत्ता खेड़ा का दौरा किया और गांव के साथ (सामान्य स्थान) पर समाचार सामग्री और पैम्फलेट, यानी अनुलग्नक ए/1 से ए/7 की फोटो प्रतियां वितरित कीं और मतदाताओं से अपील करने के लिए घर-घर भी गए। उसके लिए वोट करें. उसी समय लौटे उम्मीदवार ने मतदाताओं को समाचार सामग्री की उपरोक्त फोटो प्रतियां और पंपलेट प्रतियां, जिनमें से सभी ए/7 हैं, सौंपीं। जिन व्यक्तियों को ये फोटो प्रतियां दी गईं वे थे:—

(i) हरबिंदर पाल सिंह पुत्र स्वर्गीय संत सिंह निवासी गांव रत्ता खेड़ा।

(ii) बलदेव सिंह पुत्र बसंत सिंह निवासी ग्राम रत्ता खेड़ा।

(15) जहां तक चुनाव आयोग के पैरा 73 में दिए गए कथनों का सवाल है, वे सामान्य प्रकृति के हैं, जिसमें मतदान से एक दिन पहले प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जैसा कि वोटों की गिनती के समय आरोप लगाया गया था, ताकि उन्हें हुक द्वारा निर्वाचित घोषित किया जा सके। या बदमाश. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एचएस मत्तेवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने वोटों की गिनती के समय की गई कथित अनियमितताओं और चुनाव याचिका के कुछ पैराग्राफों के संबंध में अपना मामला छोड़ दिया है।

साथ ही मतगणना के समय हुई अनियमितताओं से संबंधित मुद्दे को भी हटा दिया गया। इसलिए, जहां तक वोटों की गिनती का सवाल है, पैरा 7 में लगाए गए आरोप, श्री एचएस मत्तेवाल के बयान को ध्यान में रखते हुए खारिज किए जाते हैं।

(16) जहां तक चुनाव याचिका के पैरा 7 में किए गए निवेदन के पहले भाग का सवाल है, यह काफी सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति का है। याचिका का पैरा 7, यदि स्वयं लिया गया है, तो याचिकाकर्ता द्वारा इस चुनाव याचिका को दायर करने के लिए कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है।

(17) जहां तक पैरा 9(i) और 9(ii) में लगाए गए आरोपों का सवाल है, वे "प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कथित तौर पर किए गए भ्रष्ट आचरण" से संबंधित हैं और जिसका विवरण याचिका के बाद के पैराग्राफ में दिया गया है। पैरा 9(i) और (ii) में लगाए गए आरोप चुनाव याचिका के बाद के पैराग्राफ में दिए गए भ्रष्ट आचरण के आरोपों के सारांशित और संक्षिप्त रूप में हैं और उन्हें रिट याचिका के अन्य पैराग्राफ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार, याचिका के पैरा 11, 12 और 14 में लगाए गए आरोपों को चुनाव याचिका के शेष पैरा के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रतिवादी 'नंबर' द्वारा कथित तौर पर किए गए भ्रष्ट

आचरण से संबंधित हैं। पैरा 10 में लगाए गए आरोप चुनाव याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन और 1980 के बाद से राजनीति में उनकी रुचि दिखाने और उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस किसान दल का महासचिव नियुक्त किए जाने के बारे में हैं। इस पैरा में कहा गया है कि याचिकाकर्ता फिरोजपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधिवत विधायक चुना गया था। जहां तक याचिका के पैरा 10 में दिए गए इन कथनों का सवाल है, उनका संबंध केवल याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत और राजनीतिक स्थिति पर है और इसे ऐसा नहीं माना जा सकता है जिससे प्रतिवादी नंबर 1 को शर्मिंदा होने की संभावना हो। इसलिए, उसमें लगाए गए आरोप खारिज किए जाने योग्य नहीं हैं।

(18) जहाँ तक अनुच्छेद S9(i), 9(ii) 12 और 14 में किए गए कथनों का सवाल है, उन्हें मुद्दे संख्या 4 के साथ लिया जाना चाहिए, जो कि चुनाव याचिका के संबंध में है जिसमें गठन के लिए आवश्यक भौतिक तथ्यों और विवरणों का अभाव है। प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव को रद्द करने के लिए कार्रवाई का पूरा कारण। तदनुसार मुद्दा नंबर 4 को विचार के लिए लिया जाना है और यदि मुद्दा नंबर 4 का फैसला प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में होता है तो दिए गए कथनों का भाग्य क्या होगा उपरोक्त पैराग्राफ में, यानी 9(i), (ii), 11, 12 और 14 पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इन पैराग्राफों को प्रभावित करने वाला प्रासंगिक विचार भ्रष्ट आचरण के अस्तित्व के संबंध में चुनाव याचिका में दिए गए दो सेटों के संबंध में किया जाना है, जिन्हें कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1/ श्री जनमेजा सिंह द्वारा अपनाया गया है।

(19) चुनाव याचिका में बताए गए भ्रष्ट आचरण के उदाहरणों का पहला सेट प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 6 फरवरी, 1997 को, यानी मतदान की तारीख से एक दिन पहले, उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुलग्नक ए1 से ए 7 की फोटो प्रतियां वितरित करने के बारे में है। जो कि 7 फरवरी, 1997 को होने वाला था। परिशिष्ट ए 1 से ए 7 की सामग्री को संक्षेप में देखना उपयोगी होगा, जिसे चुनाव याचिका के साथ संलग्न किया गया है और प्रथम दृष्टया विचार करना होगा कि क्या ये परिशिष्ट किसी भी तरह से चुनाव याचिका के लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिवादी नंबर 1 और क्या याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक ए 1 से ए 7 की फोटो प्रतियां वितरित करने में, उसकी सहमति से, प्रतिवादी नंबर 1 या उसके समर्थकों की भागीदारी के संबंध में भौतिक तथ्य और पूर्ण और बेहतर विवरण दिए हैं। इसके अलावा, इन अनुलग्नकों के कथित वितरण के कारण याचिकाकर्ता की चुनाव संभावनाओं पर यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(20) अनुलग्नक ए1, ए2 और ए3 क्रमशः 16 अगस्त, 1989, 17 सितंबर, 1989 के समाचार पत्रों 'द ट्रिब्यून' और 31 अक्टूबर, 1996 के 'द पंजाबी ट्रिब्यून' में छपे समाचारों के उद्धरण हैं। समाचार पत्र, 'द ट्रिब्यून' और साथ ही 'द पंजाबी ट्रिब्यून' पंजाब राज्य में व्यापक प्रसार में हैं। 16 अगस्त, 1989 और 17 सितंबर, 1989 को 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित समाचार आइटम किसी भी तरह से प्रतिवादी नंबर 1 से संबंधित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इन दो अनुलग्नकों (ए1और ए 2) पर प्रथम दृष्टया आरोप नहीं लगाया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकाशित कराया गया है। चुनाव याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 या उसका कोई समर्थक, उसकी सहमति से, वह व्यक्ति था जिसने इन समाचारों को प्रकाशित करवाया था। इसी तरह 'द पंजाबी ट्रिब्यून' दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 (कॉपी अनुलग्नक पी 3) में छपी खबर का श्रेय भी प्रतिवादी नंबर 1 या उसकी सहमति से उसके किसी भी समर्थक को नहीं दिया गया है।

(21) 16 सितंबर 1989 के समाचार आइटम (अनुलग्नक अल) में अकाल तख्त जत्थेदार, श्री दर्शन सिंह द्वारा पंजाब सरकार और राज्य कांग्रेस (आई) नेतृत्व के ध्यान में युवा कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर एक महिला के उत्पीड़न का मामला लाने का उल्लेख है। I)फिरोज़पुर जिले के अध्यक्ष। समाचार के तीसरे पैरा में, यह उल्लेख किया गया था:-

> “अस्पताल में भर्ती श्रीमती रूपिंदर कौर ने अपने प्रमाणित अभ्यावेदन में आरोप लगाया कि श्री रविंदर सिंह और उनके “बाहुबलियों” ने लगभग आठ महीने पहले उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। बाद में जब उन्होंने गवर्नर के सलाहकार जेएफ रिबेरो से शिकायत की तो उन्होंने जमीन वापस दिलाने में उनकी मदद की. हालाँकि, एक बार फिर कांग्रेस (आई) नेता ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था
>
> प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि वह उसे "गंभीर परिणाम" भुगतने की धमकी दे रहा था।

(22) इस समाचार के चौथे पैरा (अनुलग्नक ए.1.) में, अन्य बातों के साथ, यह आरोप लगाया गया था:-

> “दो बच्चों की मां, श्रीमती रूपिंदर कौर ने कहा कि वह और उनके भाई गुरदीप सिंह 8 सितंबर को स्कूटर पर जा रहे थे, जब श्री रविंदर सिंह के नेतृत्व में कुछ हथियारबंद व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। इससे पहले कि कुछ ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया, उन्हें राइफल की बटों और लाठियों से पीटा गया। उसके सिर पर चोटें आईं और उसे जीरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

(23) इस समाचार में श्री रविंदर सिंह का संदर्भ चुनाव याचिकाकर्ता के लिए है, जैसा कि स्वयं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। उक्त समाचार को ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि उक्त मामला अकाल तख्त जत्थेदार श्री दर्शन सिंह द्वारा उठाया गया था और संबंधित महिला, यानी श्रीमती रूपिंदर कौर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाते हुए अपना प्रतिनिधित्व दायर किया था। समाचार में सीपीआई नेता श्री सत्यपाल डांग द्वारा जांच की मांग का उल्लेख है। में जो कथन किये गये हैं।

चुनाव याचिका में किसी भी महत्वपूर्ण आरोप का अभाव है और श्रीमती रूपिंदर कौर द्वारा कथित तौर पर दिए गए प्रतिनिधित्व के पीछे या अधिकारियों के साथ मामले को उठाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 की भागीदारी के बारे में पूर्ण और बेहतर विवरण नहीं है। इसके अलावा, यह समाचार आइटम, जो वर्तमान मामले में मतदान की तारीख से बहुत पहले 16 सितंबर, 1989 को प्रकाशित हुआ था, यानी सात साल से अधिक समय पहले, फरवरी, 1997 में याचिकाकर्ता की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना नहीं थी। चुनाव. यह समाचार फरवरी, 1997 के चुनावों से बहुत दूर से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता को हराकर निर्वाचित घोषित किया गया था।

(24) अनुबंध A2, वास्तव में, 17 सितंबर, 1989 को द ट्रिब्यून में छपी खबर का खंडन है, जिसे याचिकाकर्ता श्री रविंदर सिंह बब्बल ने स्वयं प्रकाशित किया था, जो उस समय फिरोजपुर जिला युवा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस (आई). प्रतिवादी नंबर 1 को इस समाचार आइटम (अनुलग्नक ए 2) की फोटो प्रतियां प्रसारित करने से दूर-दूर तक किसी भी तरह से लाभ नहीं हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के आदेश पर प्रकाशित किया गया था। इस प्रतियोगिता में, यह पाया जा सकता है कि चुनाव याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस समाचार आइटम से जुड़े होने और दूसरे की चुनाव संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई भौतिक आरोप और पूर्ण और बेहतर विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता.

(25) अब अनुलग्नक A3 पर आते हैं, जो 31 अक्टूबर, 1996 को पंजाबी ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था, यानी मतदान की तारीख से लगभग तीन महीने पहले, जो 7 फरवरी, 1997 को हुआ था, यह एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य की पिटाई के आरोप से संबंधित है। अकाली नेता द्वारा विधायक यह समाचार तलवंडी भाई के एक संवाददाता द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल (बादल) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस्ती भाग सिंह निवासी मेहर सिंह संधू के पुत्र जतिंदर सिंह संधू द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में बताया गया था। फिरोजपुर इकाई, याचिकाकर्ता, फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक रविंदर सिंह बब्बल के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया कि रविंदर सिंह बब्बल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसके पिता श्री को चोटें पहुंचाईं। मेहर सिंह, उनकी मां परमजीत कौर, पत्नी संदीप कौर और दो बच्चे थाना सदर मोगा के इलाके में रहते हैं। समाचार के अंत में, अन्य बातों के साथ-साथ, इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया:-

> "___जब बब्बल के बंदूकधारियों ने आकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह कैंट से विधायक हैं। तब पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कर मामले को टाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली नेता होने के कारण बब्बल ने मेहर सिंह पर हमला किया है, इसलिए उनके खिलाफ धारा 307 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(26) समाचार आइटम जतिंदर सिंह संधू द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है। याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 के साथ जतिंदर सिंह संधू के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया गया है और इसके अलावा इस समाचार की फोटो प्रतियों के वितरण से प्रतिवादी नंबर 1 को लाभ मिल सकता है। दूसरे शब्दों में, इस समाचार ने पहली बार में या किसी भी दर पर प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश पर याचिकाकर्ता की चुनाव संभावनाओं को प्रभावित नहीं किया और न ही उपरोक्त चुनावों में प्रतिवादी नंबर 1 की संभावनाओं को बढ़ावा दिया।

(27) अनुलग्नक A4, द पंजाबी ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार, अनुलग्नक A3, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, का अनुवाद है।

(28) अनुलग्नक A5 एक पैम्फलेट है जिसमें फिरोजपुर के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की गई है, जो पंजाब के पांच लाख कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा चुनाव में याचिकाकर्ता, तत्कालीन मौजूदा विधायक की उम्मीदवारी का समर्थन न करने की अपील की गई थी। याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, पंजाब की ओर से यह पैम्फलेट प्रकाशित करवाया था या वह किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त पैम्फलेट के प्रकाशन से संबंधित था। चुनाव याचिका में इस पुस्तिका के प्रकाशन के संबंध में भौतिक तथ्यों और संपूर्ण विवरणों का अभाव है

और प्रतिवादी नंबर 1 को उसी के साथ जोड़ रहा है। इसके अलावा, इस पर्चे में कोई तारीख का उल्लेख नहीं है, हालांकि यह 7 फरवरी, 1997 को होने वाले मतदान को संदर्भित करता है। चुनाव याचिका के प्रयोजन के लिए यह नहीं माना जा सकता है कि चूंकि पर्चे में मतदाताओं से वोट करने की अपील की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1, यह पांच लाख कर्मचारियों के उक्त संयुक्त मोर्चा द्वारा उनकी सहमति से तैयार या जारी किया गया था। चुनाव याचिका में यह भी स्पष्ट रूप से आरोप नहीं लगाया गया है कि उक्त पर्चे से याचिकाकर्ता की चुनाव संभावनाओं पर कैसे और किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(29) जहां तक अनुलग्नक ए7 का सवाल है, यह जिला कांग्रेस कमेटी (आई), फिरोजपुर के अध्यक्ष, अर्थात् श्री गुरनैब

सिंह बराड़ द्वारा 30 जून, 1990 को जारी किया गया था। यह पत्र अखिल भारतीय राष्ट्रपति को संबोधित था। युवा कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:- फिरोजपुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह संधू उर्फ बब्बल के खिलाफ पुलिस स्टेशन घल्ल खुर्द में चोरी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इससे पार्टी की बदनामी हुई है. फिरोजपुर जिले में जिला युवा कांग्रेस पूरी तरह से अस्तित्वहीन निकाय है। इसका कोई कार्यालय नहीं है और अधिकांश ब्लॉक अध्यक्ष पद पूरे नहीं हुए हैं, पार्टी कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना एवं रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया गया. रविंदर सिंह संधू को आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में पूछताछ के लिए सीआईए स्टाफ फिरोजपुर में भी हिरासत में लिया गया था। पार्टी हित में ऐसे अवांछनीय व्यक्ति को तत्काल हटाया जाना चाहिए। अन्यथा जिले में पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह खराब हो जायेगी."

(30) जाहिर तौर पर इस पत्र को भेजने में प्रतिवादी नंबर 1 का कोई हाथ नहीं था। याचिका में इस बारे में कोई कथन नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 को यह पत्र कैसे मिला। इसके अलावा, जिला कांग्रेस कमेटी, फिरोजपुर के अध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली के अध्यक्ष को किए गए चोरी के आपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता की चुनाव संभावनाओं पर कोई सीधा असर नहीं होगा। प्रश्न में चुनाव. प्रतिवादी नंबर एक के आदेश पर तैयार और प्रसारित किए जा रहे पैम्फलेट (अनुलग्नक ए 7) के संबंध में भौतिक तथ्य और विवरण चुनाव याचिका में गायब हैं। चुनाव याचिका के प्रासंगिक पैराग्राफ में लगाए गए आरोप अनुलग्नक ए 1 से ए 7 की फोटो प्रतियों के संबंध में 6 फरवरी, 1997 को प्रतिवादी संख्या एल द्वारा और उनकी सहमति से उनके समर्थकों द्वारा प्रसारित किए गए थे।और अन्य व्यक्ति स्वभाव से सामान्य और अस्पष्ट हैं। ये समाचार और पर्चे या तो प्रतिवादी नंबर 1 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रकाशित कराए गए थे। चुनाव याचिका के पैराग्राफ 14, 14 (ए) और 15 से 27 में, निर्वाचित उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को संलग्नक एएल से ए 7 की फोटो प्रतियां सौंपने के लिए वहां उल्लिखित विभिन्न गांवों में जाने का संदर्भ दिया गया है। ऐसे कुछ मतदाताओं का उल्लेख उक्त पैराग्राफ के नीचे किया गया है। इसके अलावा, इन सभी पैराग्राफों में उपरोक्त समाचारों और पैम्फलेटों के साथ प्रतिवादी नंबर 1 की किसी भी चिंता के बारे में और याचिकाकर्ता की पूल संभावनाओं के बारे में कोई भी भौतिक तथ्य और बेहतर विवरण नहीं दिया गया है, जो अनुलग्नकों A1 से A7 के वितरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

(31) प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला दिया कि यह जरूरी है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और आगे कहता है कि उसे किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण भी देना होगा, जिसका वह आरोप लगाता है, जिसमें इस तरह के अभ्यास को करने वाले कथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा विवरण भी शामिल होना चाहिए|

(32) मनीराम याचिकाकर्ता बनाम सुरिंदर कुमार और अन्य में, प्रतिवादी (1) इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा 10 में निम्नानुसार निर्णय लिया:

"चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और इसके अलावा उसे किसी भी मामले का पूरा विवरण भी देना होगा। जिस भ्रष्ट आचरण का उसने आरोप लगाया है, उसमें ऐसे आचरण करने वाले कथित पक्षों के नाम और ऐसे आचरण के कमीशन की तारीख और स्थान का यथासंभव पूरा विवरण शामिल है। दूसरे शब्दों में, इसकी धारा 83 अनिवार्य है और इसके लिए पहले भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर यथासंभव पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है। जैसा कि सामंत एन. बालकृष्ण आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडीज आदि, एआईआर 1969 एससी 1201 में चर्चा की गई थी, "'सामग्री' शब्द से पता चलता है कि कार्रवाई का पूरा कारण तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्यों को बताया जाना चाहिए। एक भी महत्वपूर्ण तथ्य के चूक से कार्रवाई का कारण अधूरा रह जाता है और दावे का विवरण ख़राब हो जाता है।

कार्य विवरण का तात्पर्य कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर के साथ-साथ विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना है ताकि विपरीत पक्ष को यह समझ आ सके कि उसे किस मामले से निपटना होगा। भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इस प्रकार भौतिक तथ्यों में उल्लेख होगा कि तथ्य का एक बयान (जिसे निर्धारित किया जाना चाहिए) दिया गया था और यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि यह उम्मीदवार के चरित्र और आचरण को संदर्भित करता है कि यह गलत है या जिसे लौटाया गया उम्मीदवार गलत मानता है या इसे सच नहीं माना जाता है और यह याचिकाकर्ता की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए गणना की गई है। विवरण में बयान देने वाले व्यक्ति का नाम, दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार भौतिक तथ्य भ्रष्ट आचरण का आधार और कार्रवाई का पूरा कारण दिखाएंगे और विवरण कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर पेश करने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे।

(33) पैरा 12 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मदन लाई अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी (2) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और वहां से निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया (पृष्ठ 1587 पर बनाया गया): -

"भ्रष्ट आचरण के आरोप आपराधिक आरोपों की प्रकृति में हैं, यह आवश्यक है कि आरोपों में कोई अस्पष्टता न हो ताकि

(1) ए.आई.आर.1993 Pb. & Haryana 152

लौटने वाले उम्मीदवार को पता चल सके कि उसे किस मामले से निपटना है। यदि आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं और दलीलों में भ्रष्ट आचरण का विवरण नहीं दिया गया है, तो कार्रवाई के कारण के अभाव में चुनाव याचिका की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। कानून का जोर मछली पकड़ने और घूमने की पूछताछ से बचने पर है। इसलिए, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह भ्रष्ट आचरण से संबंधित दलीलों की सख्त तरीके से जांच करे।"

(34) विद्वान एकल न्यायाधीश ने ललित किशोर चतुर्वेदी बनाम जगदीश प्रसाद थडा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए, (3) शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया (पृष्ठ 1733 पर): -

“चुनाव लोकतंत्र की यांत्रिक गारंटी है और मतदाताओं के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार जनमत द्वारा सरकार के अंत तक पहुंचने का साधन है, जो मूल रूप से निष्पक्ष आलोचना पर लड़ा जाता है। इसमें भ्रष्ट आचरण का सहारा लेना विध्वंसक है,लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसका प्रभाव गहरा और व्यापक है, इसलिए, व्यक्तियों के नाम, समय और स्थान सहित इस तरह की प्रथा का पूरा विवरण निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 83 (i) (बी) द्वारा कल्पना की गई वैधानिक बाध्यता को लागू किया गया है। सख्ती से समझा गया और सटीक और विशिष्ट दलील के अभाव में यह चुनाव याचिका को कमजोर करने वाला माना गया है।"

(2) ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1577
(3) ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 1731

(35) हिन्दहरद्वारी में\लियाव। कंवल सिंह, एन (4) जबकि भौतिक तथ्यों के महत्व और भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच अंतर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में निम्नानुसार माना था: -

“मनुभाई नंदलाल अमर्सी बनाम पोपटलाल मणिलाल जोशी (1969) 3 एससीआर 217=(एआईआर 1969 एससी 734) मामले में इस न्यायालय के एक अन्य हालिया फैसले में भौतिक तथ्यों के महत्व और भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच अंतर को भी सामने लाया गया था। उस मामले में याचिका में आरोप यह था कि अपीलकर्ता या उसके चुनाव एजेंटों की सहमति से कई व्यक्तियों ने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित या प्रेरित करने का प्रयास किया कि यदि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया तो वे दैवीय नाराजगी और आध्यात्मिकता का पात्र बन जाएंगे। निन्दा. मुकदमे के अंतिम चरण में उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता को भ्रष्ट आचरण के नए विवरण जोड़कर याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी। बच्चावत, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 83 अनिवार्य थी और भ्रष्ट आचरण का विवरण पूर्ण रूप से दिया जाना था। उस मामले में कहा गया था कि यदि याचिका में पहले से ही भ्रष्ट आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है तो भ्रष्ट आचरण के विवरण के आकार में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है। स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि एक चुनाव याचिका में चुनाव को शून्य घोषित करने का प्रभाव होता है। यह एक गंभीर उपाय है. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्ट आचरण में भौतिक तथ्यों का पूर्ण विवरण होना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता को कार्रवाई का पूरा कारण मिल सके और प्रतिवादी को मामले को पूरा करने के लिए समान और पूर्ण अवसर मिल सके। आरोपों का बचाव करने के लिए. केवल यह आरोप लगाना कि प्रतिवादी ने सहायता प्राप्त की या प्राप्त की या प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास किया या क़ानून से ऐसे शब्द निकाले जिनका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि यह दिखाने के लिए तथ्य न बताए जाएं कि क्या है

वह सहायता क्या है और इस तरह की सहायता से चुनाव की संभावना को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान मामले में, यह भी आरोप नहीं लगाया गया कि प्राप्त या प्राप्त की गई सहायता शब्द देने के अलावा अन्य थी। प्रतिवादी के वकील द्वारा यह कहा गया था कि क्योंकि क़ानून वोट देने को भ्रष्ट आचरण नहीं बनाता है, इसलिए 'कोई सहायता' शब्द भौतिक तथ्यों का पूर्ण विवरण है। प्रस्तुतीकरण इस सरल कारण से भ्रामक है कि सहायता का मामला * सहायता का तरीका, सहायता का तरीका, सहायता का माप याचिका को कार्रवाई के कारण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तथ्य के विभिन्न पहलू हैं जो उत्तर की मांग करेंगे। भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जो यदि स्थापित हो जाएं तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत मिल जाएगी। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता तो क्या न्यायालय चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दे सकता था। उत्तर नकारात्मक है क्योंकि याचिका में लगाए गए आरोपों में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है।"

(36) डी इन (डॉ.टी.(श्रीमती)एनशिपरावेटसी. एचवी.एनशांति लाईखोईवालवेटसी. झम्मक लाई बनाम लक्ष्मी नारायण पांडे और अन्य, (5) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पैरा 13 में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

(4) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 515.

“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि याचिका के केवल उन हिस्सों को जिनमें भ्रष्ट आचरण के आरोप हैं और जो नियम 94 -ए और धारा 83 (1) के साथ पढ़े जाने वाले फॉर्म 25 के अनुरूप नहीं हैं, केवल उन हिस्सों को हटाने की आवश्यकता है और अन्य स्वतंत्र रूप से जारी किए गए मामलों पर मुकदमा चलाया जाना और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

इस मामले में, हालांकि उसके नामांकन की अस्वीकृति की वैधता पर अपीलकर्ता द्वारा सवाल उठाया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उच्च न्यायालय में गंभीरता से प्रचार नहीं किया गया था और अपीलकर्ता के वकील द्वारा उच्च न्यायालय में तर्क का मुख्य जोर दिया गया था। भ्रष्ट आचरण और दोष के निवारण पर था जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हमारा मानना है कि नामांकन की अनुचित अस्वीकृति के आधार पर अपीलकर्ता को चुनाव लड़ने से रोकने का सवाल गंभीर विचार के लिए नहीं उठता है। पूरी चुनाव याचिका केवल भ्रष्ट आचरण के आरोप पर ही टिकी हुई थी। नतीजतन, जब चुनाव याचिका को हलफनामे की असली प्रतिलिपि में भौतिक दोष के कारण सुनवाई योग्य नहीं माना गया, जो एक अभिन्न अंग है चुनाव याचिका का हिस्सा, चुनाव याचिका को खारिज करने को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता।”

(37) गजानन कृष्णाजी बापट और अन्य अपीलकर्ता बनाम दत्ता राघोबाजी मेगके और अन्य, उत्तरदाताओं (6) में, इसे पैरा 17 में निम्नानुसार देखा गया था: -

“17. अधिनियम की धारा 83 में प्रावधान है कि चुनाव याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और इसके अलावा उसे उस भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देना होगा जिसका उसने आरोप लगाया है, जिसमें नाम का यथासंभव पूरा विवरण भी शामिल होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाने वाले दलों की संख्या और ऐसे प्रत्येक भ्रष्ट आचरण को करने की तारीख और स्थान। इस धारा को अनिवार्य माना गया है और इसके लिए पहले भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण आवश्यक है, ताकि कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(38) एलआर शिवरामगौड़ा और अन्य बनाम टीएम चंद्रशेखर (मृत) एलआर और अन्य (7) द्वारा रिपोर्ट किए गए एक हालिया फैसले में, इसे पैरा 11 में निम्नानुसार देखा गया था: -

"11। इस न्यायालय ने बार-बार चुनाव याचिका में दलीलों के महत्व पर जोर दिया है और "भौतिक तथ्यों" और "भौतिक विवरणों" के बीच अंतर बताया है। जबकि भौतिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए दलील में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को बाद में ठीक किया जा सकता है। एक उचित संशोधन द्वारा चरणबद्ध करें।"

(39) गंजनम कृष्णाजी बापट बनाम दत्ताजी राघोबाजी मेघे के मामले को एलआर शिवरामगौड़ा के मामले (सुप्रा) में फैसले के पैरा 15 में संदर्भित किया गया था, जिसमें उक्त मामले से निम्नलिखित टिप्पणियां निकाली गई थीं: -

“भ्रष्ट आचरण के आरोप ठीक से लगाए जाने चाहिए और याचिका में ही भौतिक तथ्य और विवरण दोनों उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि कार्रवाई के पूरे कारण का खुलासा हो सके।

(6) एआईआर 1995 एससी 2284।
(7) 1999 (1)एससीसी 666।

(5) ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1691.

(40) एलआर शिवरामगौड़ा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 16, 17 और 18 में आगे कहा:-

"16. चुनाव कानून इस बात पर जोर देता है कि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को पद से हटाने के लिए, भ्रष्ट आचरण को विशेष रूप से आरोपित किया जाना चाहिए और सख्ती से साबित किया जाना चाहिए कि यह भ्रष्ट आचरण स्वयं या उसके चुनाव एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से या उसके द्वारा किया गया है। चुनाव एजेंट. संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे आरोपों को प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाए। "______________

"17. अधिनियम की धारा 83 में प्रावधान है कि चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और इसके अलावा उसे उस भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देना होगा जिसका उसने आरोप लगाया है, जिसमें नाम का यथासंभव पूरा विवरण भी शामिल होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाने वाले दलों की संख्या और ऐसे प्रत्येक भ्रष्ट आचरण को करने की तारीख और स्थान। इस धारा को अनिवार्य माना गया है और इसके लिए पहले छोटे-मोटे तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण आवश्यक है ताकि कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।"

"18. कानून के अनुसार, भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाली याचिका को एक हलफनामे द्वारा समर्थित होना आवश्यक है और चुनाव याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण के कमीशन के संबंध में अपनी जानकारी के स्रोत का खुलासा करने के लिए भी बाध्य है। चुनाव याचिकाकर्ता को उसके द्वारा लगाए गए आरोप से बांधने और किसी भी मछली पकड़ने या घूमने की जांच को रोकने और निर्वाचित उम्मीदवार को

आश्चर्यचकित होने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है।"

(41) दूसरी ओर, चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु अपीलकर्ता बनाम एम. पापैया और अन्य प्रतिवादियों (8) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पैरा 4 में, यह अंतर था अन्य बातें इस प्रकार हैं:-

"4.यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मुकदमे की प्रकृति तय करने के लिए पूरे वादपत्र को पढ़ा जाना चाहिए, न कि केवल राहत भाग को और वर्तमान मामले में वादपत्र किसी भी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ता है कि मुकदमा स्थापित करने के लिए दायर किया गया है वादी का स्वामित्व और उस आधार पर अपीलकर्ता निगम के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करना।________

(42) सबसे पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि किसी मुकदमे में दलीलों से संबंधित कानून चुनाव याचिका में दिए गए बयानों से संबंधित कानून से पूरी तरह से अलग है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उल्लिखित मामलों में स्पष्ट रूप से यह विचार किया है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों और भ्रष्ट आचरण से संबंधित विवरणों पर संक्षिप्त बयान होना चाहिए। चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा। चुनाव याचिका दायर करने के बाद भ्रष्ट आचरण से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य को स्पष्ट करने या जोड़ने वाले किसी भी आधार में संशोधन कानूनन अनुमति योग्य नहीं है। कुछ इसी तरह का प्रभाव उधव सिंह अपीलकर्ता बनाम माधव राव सिंधिया, प्रतिवादी, (9) में निर्धारित कानून है, जिसमें पैरा 30 में, इसे इस प्रकार रखा गया था: -

"30. हमें डर है, वकील द्वारा सुझाए गए पैराग्राफ की भाषा के विभाजन,

विच्छेदन, पृथक्करण और व्युत्क्रमण के बाद निर्माण की यह सरल विधि व्याख्या के कार्डिनल सिद्धांत के विपरीत है, जिसके अनुसार एक दलील को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए इसके वास्तविक आयात का पता लगाने के लिए। किसी वाक्य या परिच्छेद को काटकर संदर्भ से अलग करके पढ़ना जायज़ नहीं है। यद्यपि यह पदार्थ है, न कि केवल रूप जिस पर गौर किया जाना है, अभिवचन को उसी रूप में समझा जाना चाहिए जैसे यह शब्दों को जोड़ने या सबस्टेशन के बिना, या इसके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ में बदलाव के बिना खड़ा है। संबंधित पक्ष का इरादा, मुख्य रूप से, समग्र रूप से उसकी दलील के कार्यकाल और शर्तों से प्राप्त किया जाना है।

(43) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य अधिकार राम तेज तिवारी, याचिकाकर्ता बनाम श्रीमती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित है। विजया लक्ष्मी, प्रतिवादी, (10) जिसमें पैरा-17, 22 और 23 में यह देखा गया: -

"17. अगली ग्राउंड संख्या 'बी' पर विचार करते हुए प्रासंगिक कथनों को याचिका के पैरा 25 से 29 और अनुसूची 'ए' में निहित पाया जाना चाहिए। आरोप यह है कि प्रतिवादी और उसके चुनाव एजेंट ने मतदाताओं को सीधे वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उपहार, प्रस्ताव और संतुष्टि के वादे करके अधिनियम की धारा 123 (1) के अर्थ के तहत रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण किया।

प्रतिवादी के लिए. प्रतिवादी के लिए श्री पांडे का तर्क है कि अधिनियम की धारा 83 (1) (बी) के तहत शामिल किए जाने के लिए आवश्यक प्रासंगिक विवरणों की दलीलों में कमी है। 0.6 आर. 2(1), सीपीसी धारा के प्रावधानों के आधार पर

(9) एआईआर 1976 एस.सी 744
(10) एआईआर 1986 इलाहाबाद 325

83 (1) (ए) में कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर चुनाव याचिकाकर्ता भरोसा करता है। उप-धारा का खंड (बी)। धारा 83 का (1) निषेध करता है कि एक चुनाव याचिका में किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जिस पर वह लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देता है, जिसमें ऐसा करने वाले कथित दलों के नामों का यथासंभव पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। भ्रष्ट आचरण और ऐसे प्रत्येक आचरण के कमीशन की तारीख और स्थान। यह कमोबेश O. VI पर निर्भर करता है। संहिता के आर 4. इसमें कोई विवाद नहीं है कि धारा 83 (1) (बी) में 'सहित' शब्द के बाद जो आता है वह संपूर्ण नहीं है। इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति विस्तार की है, इसमें केवल वही शामिल नहीं है जो खंड में वर्णित है, बल्कि वह सब शामिल है जो कथित भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देता है। ब्रूस वी. ओधम्स प्रेस लिमिटेड (1936) 1 ऑल ईआर 287 में, स्कॉट, एलजे ने इस प्रकार 'भौतिक तथ्यों' और 'विशेषताओं' के बीच अंतर किया है-

"आर. 4 में मुख्य प्रावधान यह है कि दावे के बयान में भौतिक तथ्य बताए जाने चाहिए। शब्द "सामग्री" का अर्थ कार्रवाई का पूरा कारण तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक है, और यदि कोई भी "सामग्री" कथन छोड़ दिया जाता है, तो दावे का कथन खराब है; पुरानी शब्दावली में यह "विलंबनीय" है, और नए में बीएससीओ XXV के तहत "हटाए जाने योग्य" है। आर. 4. देखें फिलिप्स बनाम फिलिप्स (1978) 4 क्यूबीडी 127 या "दावे का एक और बेहतर विवरण" आर. 7 के तहत आदेश दिया जा सकता है।

R. 6 के अंतर्गत "विवरण" का कार्य काफी भिन्न है। दावे-अंतराल के विलम्बनीय विवरण में भौतिक अंतराल को भरने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसे विभिन्न भौतिक तथ्यों के उचित बयानों से भरा जाना चाहिए जो एक साथ वादी की कार्रवाई का कारण बनते हैं। विवरण के उपयोग का उद्देश्य प्रतिवादी पर निष्पक्षता और न्याय के लिए लगाई गई दलील की एक और पूरी तरह से अलग आवश्यकता को पूरा करना है। उनका कार्य वादी की कार्रवाई के कारण की तस्वीर को पर्याप्त रूप से विस्तृत जानकारी से भरना है ताकि प्रतिवादी को उस मामले के बारे में सतर्क रखा जा सके जिसे उसे पूरा करना है और उसे मुकदमे के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना है।

"22. आदेश VI, आर 16 (बी), सीपीसी, उन दलीलों को खारिज करने की अनुमति देता है जो अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई को शर्मिंदा कर सकती हैं। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (1971) वॉल्यूम I पृष्ठ 739 के अनुसार अभिव्यक्ति "शर्मनाक" का अर्थ है, "भ्रम या कठिनाई पर संदेह करना" ऐसा कहा गया है कि किसी भी प्रतिवादी के लिए कुछ भी अधिक शर्मनाक नहीं है।

ऐसे कथन जो अप्रासंगिक हो सकते हैं और इसलिए, प्रतिवादी को नहीं पता कि क्या करना है। प्रत्येक पक्ष को अपने विरुद्ध अपना मामला सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार है ताकि उसे इसे पूरा करने में शर्मिंदा न होना पड़े: डेवी बनाम गैरेट (1877) 7 अध्याय डी 473 पृष्ठ पर। 483।"

"23. हालाँकि, स्थापित दृष्टिकोण यह है कि दलीलों को जमीनी अस्पष्टता के आधार पर खारिज करने से पहले याचिकाकर्ता को कथित भ्रष्ट आचरण के विवरण में संशोधन करने या बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: और गैर-अनुपालन की स्थिति में उस आदेश के साथ न्यायालय उन आरोपों को खारिज कर सकता है जो अस्पष्ट हैं: बलवान सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण (1960) 22 एली एलआर 273 एट 281: (एआईआर 1960 एससी 770 पृष्ठ 774 पर): हरीश चंद्र बाजपेयी बनाम त्रिलोकी सिंह (सुप्रा)। हालाँकि एस. 83 (3) को हटा दिया गया है, न्यायालय याचिकाकर्ता को या तो याचिका में संशोधन करने या विवरण प्रस्तुत करने या संबंधित पैराग्राफ को हटाने का विकल्प देना चाहता है। अमीन लाई बनाम हुन्ना माई, एआईआर 1965 एससी

1243। भ्रष्ट का विवरण याचिका में कथित प्रैक्टिस को उचित मामलों में संशोधन डीपी मिश्रा बनाम कमल नारायण शर्मा, एआईआर 1970 एससी 1^77 द्वारा पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। यह O.VI के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 86(5) के अनुरूप होगा। आर.5, सिविल प्रक्रिया संहिता।”

(44) कानून के संबंध में स्थिति डॉ. (श्रीमती) शिप्रा के मामले (सुप्रा), सरदार बलदेव सिंह मान के मामले (सुप्रा) और एल.आर. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसलों से अच्छी तरह से तय और निष्कर्ष पर पहुंची है। शिवरामगौड़ा का मामला (सुप्रा)। भ्रष्ट आचरण के आरोप को साबित करने के लिए सबूत के मानक की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वर्तमान चरण में याचिकाकर्ता मुकदमे में नहीं गया है।

(45) अब भ्रष्ट आचरण के दूसरे आरोप पर आते हैं यानी कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने समर्थकों को दी गई रिशवत को मतदाताओं को उनके (प्रतिवादी नंबर 1 के) पक्ष में वोट डालने के लिए वितरित करने के लिए दिया गया था। कंडिका संख्या 28 से 39 तक अर्थात 12 कंडिका में शाम करीब 7.30 बजे निर्वाची प्रत्याशी द्वारा अपने समर्थकों के साथ गांव झोले हरी हर में जाने और रुपये देने का जिक्र है. श्री हरि सिंह, पूर्व-सरपंच, को एक लाख रुपये दिये, फिर रात करीब साढ़े आठ बजे गांव सांडे हाशिम पहुंचे। जगीर सिंह के बेटे गुरसेवक सिंह को 40,000 रुपये दिए, फिर रात करीब 9 बजे गांव वलूर पहुंचे और रुपये दिए। नज़र सिंह के पुत्र बलदाव सिंह को 30,000; फिर रात करीब साढ़े नौ बजे गांव यारेशाहवाला पहुंचे और रुपये दिए। बाज सिंह के पुत्र बोहर सिंह को 40,000; फेन से गांव साधु शाह वाला

रात करीब 10 बजे रुपये दिए। धरम सिंह, पूर्व-सरपंच को 35,000; फिर रात करीब 10.30 बजे गांव नाजूशाह मिश्रीवाला पहुंचे और रुपये दिए। जसवन्त सिंह के पुत्र कुलबीर सिंह को 30,000; फिर रात करीब 11 बजे गांव शेर खां पहुंचे और रुपये दिए। दर्शन सिंह, पूर्व-सरपंच को 80,000; फिर रात करीब 11.30 बजे गांव तख्तूवाला जाकर रुपये दे दिए। 20,000 से श्री. बग्गा सिंह के पुत्र गुरचरण सिंह; फिर 7 फरवरी, 1997 को लगभग 12.15 बजे ग्राम जमीत पुर ढेरू गए और रुपये दिए। बग्गा सिंह के पुत्र दर्शन सिंह को 40,000; फिर 7 फरवरी, 1997 को लगभग 1.15 बजे ग्राम सोढ़ी नगर गए और रुपये दिए। कुन्दन सिंह के पुत्र मोहिंदर सिंह को 1.80 लाख; फिर रात करीब 1.45 बजे गांव कुलगढ़ी पहुंचे और रुपये दिए। बख्तावर सिंह के बेटे हरजिंदर सिंह को 40,000 और फिर 7 फरवरी, 1997 को लगभग 2.15 बजे गांव लोहगढ़ में जाकर रुपये दिए। बग्गा सिंह के पुत्र मल्कियत सिंह को 80,000 रु. दिए।

(46) उपर्युक्त 12 पैराग्राफ और पैराग्राफ में से प्रत्येक में (जिसमें इन 12 पैराग्राफों के कथनों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है), दो व्यक्तियों के नाम, जो कथित तौर पर संबंधित पैराग्राफ में नामित व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित थे, जिन्हें राशि का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 और जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में अपना वोट देने का वादा करने के लिए रिश्वत की पेशकश स्वीकार नहीं की, का उल्लेख किया गया है। ग्रामवार इन गवाहों के नाम इस प्रकार हैं:-

गांव झोके हरी हर में लखबीर सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह और जस्सा सिंह पुत्र टेक सिंह।

चमकौर सिंह पुत्र नायब सिंह और पृथी सिंह पुत्र सोहन सिंह गांव सांडे हासम में।

वलूर गांव में लखबीर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह और जीत सिंह पुत्र पृथी सिंह।

गांव यारेशाहवाला में चानन सिंह के पुत्र मेजर सिंह और मुनशा सिंह के पुत्र शेर सिंह।

गांव साधु शाह वाला में नत्था पुत्र बीला और बलविंदर सिंह पुत्र बख्शीश सिंह;

गाँव मिश्रीवाला में तरलोक सिंह के पुत्र कुलविंदर सिंह और दर्शन सिंह के पुत्र नछत्तर सिंह;

शेर खान गांव में पाला सिंह के पुत्र करनैल सिंह और दारा सिंह के पुत्र मोहिंदर सिंह;

'हंस राज पुत्र चुन्नी लाई और जीत सिंह पुत्र ला सिंह ग्राम तख्तूवाला में;

.जगीर सिंह पुत्र बिशन सिंह और बलकार पुत्र शिंगारा सिंह गांव जमीतपुर ढेरू में;

सोढ़ी नगर गाँव में जीत सिंह के पुत्र दरबारा सिंह और ठाकुर सिंह के पुत्र सुरजीत सिंह;

कुलगढ़ी गांव में जगतार सिंह पुत्र हाकिम सिंह और सुखमंदिर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह;

गांव लोहगढ़ में अजीत सिंह का बेटा सुच्चा सिंह और बग्गा सिंह का बेटा जागीर सिंह।

(47) गाँवों में होने वाली घटनाएँ पैराग्राफ 28 से 39 एक ही भाषा में दी गई हैं, लेकिन गाँव का नाम बदलने, गाँव में आने का समय, संबंधित व्यक्ति को भुगतान की गई राशि और दो गवाहों, जिन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, के बारे में जानकारी दी गई है। जो उसी। सबसे पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि पैरा 28 से 39 तक शुरू होने वाले प्रत्येक पैराग्राफ के नीचे नामित दो गवाहों के बारे में कहा जाता है कि वे संबंधित व्यक्ति के पास गए थे, जिसे कथित तौर पर पैसे का भुगतान किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ बुलाए जाने पर, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह जरूरी है कि उपरोक्त प्रत्येक गांव में दो गवाहों के ये सेट मौजूद नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त गांवों के दौरे के समय और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसमें नामित व्यक्ति को राशि के कथित भुगतान को नहीं देखा और न ही उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 और संबंधित के बीच कोई बातचीत सुनी। इन पैराग्राफों में उल्लिखित व्यक्ति, जिसे कथित तौर पर राशि का भुगतान किया गया था। उदाहरण के लिए, पैरा 28 में इसे निम्नानुसार बताया गया है:-

"उसी दिन यानी 6 फरवरी, 1997 को उपर्युक्त समर्थकों के साथ लौटे उम्मीदवार ने शाम लगभग 7.30 बजे झोले हरि हर गांव का दौरा किया और रुपये सौंपे। श्री हरि सिंह को एक लाख , पूर्व सरपंच ने शपथ लेकर उक्त धनराशि स्वीकार कर ली और पांच सौ वोट देने का वादा किया। इसके बाद श्री. हरि सिंह, पूर्व सरपंच ने कई मतदाताओं की बैठक बुलायी और रुपये दिये पांच सौ मतदाताओं में से प्रत्येक को शपथ पर 200 रुपये दिए गए और फिर अगली सुबह, यानी 7 फरवरी, 1997 को उन सभी व्यक्तियों ने, जिन्होंने शपथ पर पैसे स्वीकार किए थे, निर्वाचित उम्मीदवार के लिए मतदान किया। गांव के कुछ लोगों ने किसे वोट देने के लिए पैसे लेने से इनकार कर दिया ।

श्री हरि सिंह पूर्व. सरपंच. द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग ले रहे हैं कुछ व्यक्तियों के नाम नीचे दिये गये हैं.—

1. अंग्रेज सिंह के पुत्र लखबीर सिंह;

2. जस्सा सिंह पुत्र टेक सिंह निवासी गांव झोके हरी हर। "

(जोर मेरे द्वारा दिया गया है)।

(48) 'इसके बाद' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दो गवाह, जिन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था, उस समय उपस्थित नहीं थे जब गांव में संबंधित नामित व्यक्ति को समर्थन देने का वादा करने के लिए कथित तौर पर राशि का भुगतान किया गया था। उसमें उल्लिखित मतदाताओं की संख्या। दूसरे शब्दों में, इन पैराग्राफों में उस व्यक्ति के संबंध में भौतिक तथ्यों का अभाव है, जिसके समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 ने, उपरोक्त प्रत्येक गांव में अपनी कथित यात्रा के दौरान, अपने समर्थक से मुलाकात की और उसे और बाद वाले को राशि का भुगतान किया, यानी वह व्यक्ति जिसने स्वीकार किया। प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में वोट डालने का आश्वासन दिया गया राशि। इसके अलावा, प्रश्न में चुनाव में उक्त गांवों में एक भी व्यक्ति, यानी एक मतदाता के नाम का उल्लेख नहीं है, जिसने अपना वोट डालने के लिए रिश्वत स्वीकार की थी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में मतदान करें।

(49) चुनाव याचिका के पैरा 40 में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित कथन दिये:-

"पैरा 28 से 39 में उल्लिखित सामग्री से यह संदेह से परे स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने रुपये का भुगतान करके 3575 वोट खरीदे हैं। निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 7.15 लाख रुपये खर्च किए और लगभग पूरी रात निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त हिस्सों में धन बांटने में बिताई और किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहे।'

(50) चुनाव याचिका के पैरा 41 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था:-

"प्रतिवादी नंबर 1 अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त था कि मतदान के एक दिन बाद, प्रतिवादी नंबर 1 दाना मंडी (अनाज बाजार), फिरोजपुर कैंट गया। और खुले तौर पर चुनौती दी कि कोई भी निकाय शर्त लगा सकता है कि वह प्रतिवादी नंबर 1 होगा जो चुना जाएगा क्योंकि उसने 3,575 वोट खरीदे हैं और रुपये खर्च किए हैं। 7.15 लाख।"

(51) इस पैरा में आगे कहा गया है कि उनकी चुनौती पर निम्नलिखित चार व्यक्तियों ने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ शर्त लगाई:-

1. बेअंत सिंह, सरपंच, गांव वलूर निवासी;
2. दरबारा सिंह पुत्र अजीत सिंह, निवासी ग्राम सोढ़ी नगर;
3. सरदूल सिंह, सरपंच, गांव सांडे हाशिम निवासी; और
4. मलकियत सिंह, सरपंच, गांव कामघर निवासी।

(52) प्रतिवादी नंबर 1, यह आगे बताया गया, फिर उसके घर गया और एक लाख रुपये लाया और Ch. जगदीश दाना मंडी, फ़िरोज़पुर कैंट की कमीशन एजेंट की दुकान पर जमा कर दिया। तथा उपरोक्त चारों व्यक्तियों ने चौधरी जगदीश की दुकान पर एक लाख रुपये भी जमा कर दिये। और यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और उपर्युक्त चार व्यक्तियों द्वारा जमा की गई राशि प्रतिवादी क्रमांक 1 को दी जाएगी यदि वह निर्वाचित होता है, लेकिन यदि वह हार जाता है तो राशि उपरोक्त को भुगतान की जाएगी -चार व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह दांव 8 फरवरी 1997 को अपराह्न 3.30 बजे लगा क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 को निर्वाचित घोषित किया गया था इसलिए उसने दो लाख रुपये की राशि चौधरी जगदीश, दाना मंडी, फिरोजपुर कैंट की दुकान से ले ली।

(53) याचिका के पैरा 41 में दिए गए कथन काफी हद तक पैरा 28 से 39 में दिए गए कथनों और पैरा 40 में संक्षेपित किए गए कथनों पर निर्भर करते हैं। यदि उपरोक्त पैरा (28 से 40) में दिए गए कथन कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो दिए गए कथन पैरा 41 में स्वतः ही सूट का पालन होगा। दूसरे शब्दों में, पैरा 41 में दिए गए कथनों से, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कार्रवाई का कारण था, यह दिखाने के लिए कि उत्तरदाता ने मतदाताओं को रिश्वत की पेशकश करके भ्रष्ट आचरण में लिप्त था क्योंकि पेशकश का आरोप मतदाताओं को रिश्वत मोटे तौर पर याचिका के पैराग्राफ 28 से 40 में दी गई दलीलों पर विचार करने से प्रभावित होगी।

(54) कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मणि राम (सुप्रा) के मामले में इस पहलू पर विचार किया और पैरा 14 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"जहां रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा किए जाने का आरोप लगाया गया था, वहां इस आशय का कोई सबूत नहीं था कि रिश्वत की पेशकश उन व्यक्तियों को की गई थी जो मतदाता थे या जिन व्यक्तियों ने वास्तव में धन प्राप्त किया था वे मतदाता थे, या आगे का तथ्य यह है कि याचिका में ऐसी कथित रिश्वत लेने वालों में से किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि भ्रष्ट होने का उक्त आरोप

अभ्यास कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है, और इसलिए, चुनाव याचिका उस आधार पर खारिज करने योग्य थी।

(55) मनी राम (सुप्रा) के मामले में, वर्ष 1991 में कैथल विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता मनी राम द्वारा याचिका में लगाए गए आरोप थे कि निर्वाचित उम्मीदवार सुरिंदर कुमार ने धारा में परिभाषित रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण किया था। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से धन वितरित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 123। इस संबंध में तर्क दिया गया कि सुरिंदर कुमार ने रुपये दिए थे। श्री चंद के बेटे सतपाल और टेक चंद के बेटे सतपाल को हरिजन कॉलोनी में अपने लिए वोट हासिल करने के लिए 25,000 रुपये दिए। यह रकम 19 मई 1991 को रात करीब 10 बजे 132/5, सीवन गेट, कैथल में दी गई। यह रकम सुभाष मल्होत्रा की मौजूदगी में दी गई। सुरिंदर कुमार ने दोनों सतपालों को यह पैसा उन लोगों के बीच बांटने के लिए कहा था जिन्होंने उसे वोट देने का वादा किया था। इसके बाद दोनों सतपाल अर्जुन नगर इलाके में गए और बलवान सिंह और राम सरन से संपर्क किया। वे इलाके में घूमे और पुरुष सदस्यों को बलवान सिंह के घर के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाया। करीब 15/20 मिनट बाद वहां 250 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई. सतपाल उर्फ पाला ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वह सुरिंदर कुमार के कहने पर वहां आया था, जिन्होंने उन्हें अपने हरिजन भाइयों की मदद के लिए भेजा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग सुरिंदर कुमार को वोट देने का वादा करेंगे उन्हें रुपये दिए जाएंगे। 100 प्रत्येक. इसके बाद उन्होंने उन लोगों से हाथ उठाने को कहा जो पैसे चाहते थे और जिन्होंने सुरिंदर कुमार को वोट देने का वादा किया था। »बहुत से लोगों ने ऐसा किया. फिर उन्हें एक-एक करके बुलाया गया और रुपये दिए गए। सुरिंदर कुमार को वोट देने का वादा करने के बाद उन्होंने 100-100 रुपये दिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें इसकी जानकारी 17 जून 1991 को शाम करीब 5 बजे श्री चंद के बेटे सतपाल से उनके आवास पर मिली।

(56) मनीराम के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा 14 में आयोजित उक्त चुनाव याचिका में दिए गए अनुमानों का मूल्यांकन करते हुए निम्नानुसार बताया: -

"अब कानून के संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वतखोरी के कथित भ्रष्ट आचरण के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दावों का मूल्यांकन और आकलन करने की ओर मुड़ते हैं, जैसा कि तय किया गया है, याचिका को पढ़ने से पता

> चलेगा कि आवश्यक सामग्री और विवरण उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं। इस आरोप के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने रुपये का भुगतान किया। हरिजन कॉलोनी से वोट खरीदने के लिए दो सतपालों को 25,000 रुपये देने के मामले में, इस आशय के किसी भी दावे के अभाव से भौतिक महत्व की चूक हो जाती है कि रिश्वत की पेशकश उन व्यक्तियों को की गई थी जो मतदाता थे या जिन व्यक्तियों ने वास्तव में धन प्राप्त किया था, मतदाता थे.

इस संबंध में जो बात सामने आती है, वह यह है कि याचिका में ऐसे किसी भी कथित रिश्वत प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिया गया है। इस स्थिति में इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि यह आरोप प्रतिवादी के लिए जवाब देने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है।"

(57) मेरे सुविचारित विचार में, मौजूदा मामले में चुनाव याचिका में दिए गए दावे उस व्यक्ति के बारे में उल्लेख से भी कम हैं, जिसकी उपस्थिति में प्रतिवादी नंबर 1 ने संबंधित गांवों में संबंधित पैराग्राफ में नामित व्यक्तियों को राशि का भुगतान किया था और नाम उन व्यक्तियों की, जिन्होंने वास्तव में रिश्वत प्राप्त की थी और प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में मतदान करने का वादा किया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में आरोपों में मनीराम के मामले में तथ्यों की तुलना में पूर्ण और बेहतर विवरणों की बहुत अधिक कमी है (सुप्रा)।

(58) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय है कि लौटे उम्मीदवार/प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा रिश्वत की पेशकश और संबंधित गांवों के मतदाताओं द्वारा वोट देने के वादे के साथ इसकी स्वीकृति के संबंध में दिए गए दावे प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में संपूर्ण विवरणों का अभाव है और इस प्रकार याचिका में भौतिक तथ्यों और विवरणों के संक्षिप्त विवरण का अभाव है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि चुनाव याचिका में उसके भ्रष्ट आचरण के संबंध में एक भी भौतिक तथ्य का अभाव है, तो दोष चुनाव याचिका की जड़ तक चला जाता है और उसे खारिज कर दिया जा सकता है।

(59) परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि चुनाव याचिका कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है और उस आधार पर इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक मुद्दे तदनुसार प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में तय किए जाते हैं और परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसमें कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है:

एस.सी.के.

वीके बाली और बी राय के समक्ष

मलकीयत सिंह, -याचिकाकर्ता

बनाम

पीएसईबी और अन्य,-प्रतिवादी

CWP No. 16989 of 1998

21 जनवरी 1999

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद,। 226—पीएसईबी नीति निर्देश दिनांक 8जुलाई, 1994—नौकरी प्रदान करने के लिए बोर्ड* का नीतिगत निर्णय ।